an>

Title: Need to make 'Agriculture' a compulsory subject in School education.

श्री राजीव सातव (हिंगोली) ः भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। पर बात जब कृषि शिक्षा की आती है, तो सूरत अलग नज़र आती है। हायर सैकेंडरी स्तर पर कृषि के पाठ्यक्रम में होने के बावजूद इस पर न सरकार का ध्यान है न ही पढ़ने-पढ़ाने वालों का। स्कूल के बाद पढ़ाई जारी न रखने वाले अधिकांश छात्र खेती-किसानी में लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए न तो उन्हें औपचारिक ज्ञान होता है न कोई प्रशिक्षण। परंपरागत तौर पर जो कुछ सीखा वही उसका ज्ञान है।

सी.बी.एस.ई. के अलावा कई राज्यों के स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कृषि को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। वैकल्पिक विषय होने के अलावा कृषि बागवानी के रूप में वोकेशनल कोर्स भी मौजूद हैं। मगर हायर सैकेंडरी स्तर पर दो फीसदी से भी कम छात्र कृषि की पढ़ाई करते हैं। कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलनी है तो हाई स्कूल स्तर पर पाठ्यक्रम में कृषि की पढ़ाई को फोकस में लाना होगा।

कृषि क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाआंो और कौशल विकास के दौर में अब कृषि को फोकस में लाया जाना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पर उद्यमशीलता को कोर्स में शामिल करने की वकालत हो रही है। कृषि शिक्षा के साथ उद्यमशीलता को जोड़ने से आश्चर्यजनक परिणाम निकल सकते हैं।

आज हायर सैकेंडरी स्तर पर वही लोग कृषि की पढ़ाई करते हैं, जिन्हें कॉलेज में इसकी पढ़ाई करनी होती है पर कृषि के अधिकांश ग्रेजुएट भी खेती के लिए इसकी पढ़ाई नहीं करते। वे उच्च शिक्षा और रोज़गार के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। हायर सैकेंडरी स्तर पर अच्छे सिलेबस, रोज़गारपरक प्रैक्टिकल के साथ इस विषय की पढ़ाई करवाई जाए, तो कृषि के बारे में बुनियादी जानकारी होने के कारण इन सभी माध्यमों के प्रति युवाओं की रूचि बढ़ेगी। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी कोशिशों के अलावा जनमत बनाने की भी जरूरत होगी।

अभी संपन्न हुए पेरिस सम्मेलन में भी विकसित और विकासशील देशों ने खेती पर नए सिरे से ध्यान देने की बात की थी। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि स्कूली स्तर पर कृषि शिक्षा की पढ़ाई अनिवार्य करें।